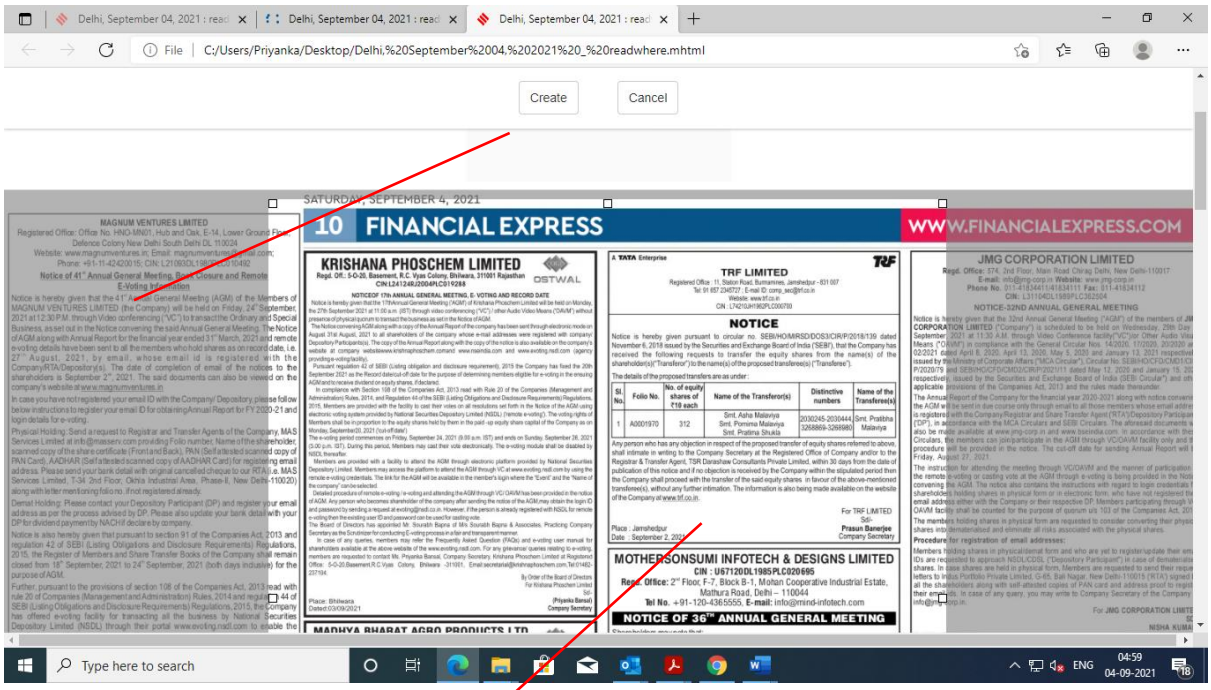
Delhi, September 04, 2021 : read
Delhi, September 04, 2021 : read
Delhi, September 04, 2021 : read
File | C:/Users/Priyanka/Desktop/Delhi,%20September%2004,%202021%20_%20readwhere.mhtml
Create
Cancel
SATURDAY, SEPTEMBER 4, 2021
10 FINANCIAL EXPRESS
WWW.FINANCIALEXPRESS.COM
MAGNUM VENTURES LIMITED
KRISHANA PHOSCHEM LIMITED
TRF LIMITED
NOTICE
JMG CORPORATION LIMITED
NOTICE-32ND ANNUAL GENERAL MEETING
MOTHERSONSUMI INFOTECH & DESIGNS LIMITED
NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING
Type here to search
ENG
04:59
04-09-2021

अप्रेल-जून 2021 क्वार्टर

होम सेल्स सालाना आधार पर दोगुना बढ़ी

नई दिल्ली/पीटीआई

देश के आठ प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री संख्या के लिहाज से पिछले साल के निम्न तुलनात्मक आधार के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दोगुने से अधिक 6.85 करोड़ वर्ग फुट रही। हालांकि, कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण मांग पिछली तिमाही के मुकाबले 19 प्रतिशत घटी है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने यह कहा।

तिमाही दर तिमाही आधार पर यदि बात की जाये तो मकानों की बिक्री देश के आठ प्रमुख शहरों में 2021-22 की पहली तिमाही में 19 प्रतिशत घटकर 6.85 करोड़ वर्ग फुट रही। वहीं इससे पिछली तिमाही यानी वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में यह 8.47 करोड़ वर्ग फुट रही थी। इसका कारण महामारी की दूसरी लहर है।

तिमाही दर तिमाही आधार पर गिरावट की वजह 2020-21 की चौथी तिमाही में उच्च

तुलनात्मक आधार भी है।

इक्रा के अनुसार, ''हालांकि,अगर 2020-21 की पहली तिमाही से तुलना की जाए तो रिहायशी मकानों की 3.37 करोड़ वर्ग फुट बिक्री की तुलना में जून 2021 को समाप्त तिमाही में बिक्री दोगुने से अधिक रही है।''

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि तेजी से टीकाकरण और अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से खोले जाने से अल्प अवधि से लेकर मध्यम अवधि में बिक्री में सुधार की संभावना है।

इक्रा ने कहा कि मांग बनी हुई है। इसका कारण ब्याज दर का कई साल के न्यूनतम स्तर पर होना और घर से काम करने की वजह से लोगों की बड़े मकानों की इच्छा होना है।

इक्रा के क्षेत्र प्रमुख और सहायक उपाध्यक्ष कपिल बंगा ने कहा, ''दूसरी लहर का प्रभाव उतना व्यापक नहीं रहा जितना कि पहली लहर में देखने को मिला। इसकी वजह कई क्षेत्रों में कर्मचारियों के घर से काम करते रहना, पाबंदिया स्थानीय स्तरों पर लगाये जाने तथा भविष्य के आय स्तर तथा स्थिरता को लेकर एक निश्चितता का होना रहा।''

उन्होंने कहा कि खासतौर से आईटी और आईटी से जुड़ी सेवाओं क्षेत्र का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। इस क्षेत्र में नई भर्तियां हुई। इस क्षेत्र के कर्मचारियों की ओर से मांग में तेजी रही।

Data Insights

Compiled by **Nafanuksan Research**

Comparative analysis of telecom players (1QFY22 numbers)

	UOM	Bharti	VIL	RJio
Financial Matrix				
Revenues	INR m	2,68,536	91,523	1,79,940
Revenue Growth (QoQ)	%	4.3	-4.7	3.7
Network Cost	INR m	57,973	24,927	59,730
Network Cost (% of Rev)	%	21.6	27.2	33.2
Network Cost (QoQ)	%	-2.0	16.7	3.8
EBITDA	INR m	1,29,803	37,077	86,170
EBITDA Margin	%	48.3	40.5	47.9
EBITDA Growth (QoQ)	%	5.3	-15.9	3.9
Finance Cost	INR m	39,773	51,949	8,210
PAT	INR m	9,414	-73,191	35,010
PAT Margins	%	3.5	-80.0	19.5
Pat Growth (QoQ)	%	-37.7	4.2	4.2
Operating Matrix				
ARPU	INR	146	104	138
ARPU Growth (QoQ)	%	0.7	-2.8	0.1
Subscriber Base	mn	321	255	441
Net Adds	mn	-0	-12	14
Churn	%	2.8	3.5	1.0
Total Data Volume	mn MB	1,07,71,051	54,97,000	2,03,00,000
Total Voice Traffic (MoN)	mn Mins	10,02,263	5,03,057	10,60,000
Wireless Broadband Subscribers	mn	194	121	437
Wireless broadband Subscribers Adds	mn	5	-2	14
Active Sub Market Share	%	34.9	24.5	34.6
4G Subscribers	mn	184	113	441
Total Cell Sites	Nos	2,19,310	6,27,788	-
Cell Sites Additions (QoQ)	Nos	2,409	-5,346	-

Source : Motilal Oswal Financial Services

इंपोर्टेड इक्यूपमेंट्स का इस्तेमाल कर बने 25 टेलीकॉम प्रोडक्ट्स होंगे सरकारी खरीद के पात्र

नई दिल्ली/पीटीआई। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने सैटेलाइट फोन, ब्रॉडबैंड उपकरण, ऑप्टिकल फाइबर केबल सहित 25 दूरसंचार उत्पादों की एक सूची जारी की है, जिनमें आयातित कलपुर्जों का इस्तेमाल किये जाने के बावजूद उन्हें स्थानीय उत्पाद माना जाएगा।

इस अधिसूचना के साथ सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 का पालन करते हुए भारतनेट, बीएसएनएल, रेलवे आदि की परियोजनाओं में आयातित घटकों से दूरसंचार उत्पाद बनाने वाली कंपनियां से खरीद की जा सकेगी।

अधिसूचना में कहा गया, ''यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सर्फेस माउंट प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए मुद्रित सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए) और आयातित या घरेलू रूप से विनिर्मित घटकों और कलपुर्जों का परीक्षण भारत में किया जाता है, तो आयातित या घरेलू रूप से विनिर्मित भागों और घटकों को स्थानीय सामग्री के लिए योग्य माना जाएगा।''

विदेशी विनिर्माताओं नोकिया, एरिक्सन, सिस्को आदि ने इससे पहले मांग की थी कि उन्हें घरेलू दूरसंचार गियर विनिर्माताओं के समान माना जाना चाहिए। अधिसूचना में कहा गया है, ''जब सेमिकंडक्टर फैब (इलेक्ट्रानिक चिप प्लांट) भारत में परिचालन में आ जायेगा तबि इसकी समीक्षा की जायेगी।''

इस समय सभी इलेक्टमनिक और दूरसंचार उपकरण निर्माता अपने उत्पाद में इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्टमनिक चिप का आयात करते हैं। बहरहाल, टाटा समूह ने देश में सेमिकंडक्टर कारखाना लगाने में रुचि दिखाई है।

रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल का पूर्ण नियंत्रण हासिल किया

नई दिल्ली/पीटीआई। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस रिटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने जस्ट डायल का पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। फर्म की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने जुलाई में 3,497 करोड़ रुपये में जस्ट डायल में नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद ''आरआरवीएल ने सेबी के अधिग्रहण विनियमों के अनुसार एक सितंबर 2021 से जस्ट डायल लिमिटेड का पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है।'' आरआरवीएल ने 20 जुलाई 2021 को जस्ट डायल के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी वी एस एस मणि से एक थोक सौदे में कंपनी के 10 रुपये चुकता कीमत वाले 1.31 करोड़ शेयर 1,020 रुपये प्रति शेयर की दर से अधिग्रहण किए थे।

कुल मिलाकर आरआरवीएल के पास जस्ट डायल के 40.90 प्रतिशत शेयर हैं। आरआरवीएल अब जस्ट डायल के अन्य शेयरधारकों से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए खुली पेशकश करेगी। आरआरवीएल ने कहा है कि जस्ट डायल में निवेश अपने लाखों साझेदार व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए डिजिटल परिवेश को और मजबूत बनाकर नए कारोबार को लेकर कंपनी की प्रतिबद्धता को बताता है। उल्लेखनीय है कि जस्ट डायल ने हाल ही में अपना बी 2 बी (कंपनियों के बीच) मार्केटप्लेस मंच जेडी मार्ट शुरू किया है जो देश में निर्माताओं, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को इंटरनेट के लिए तैयार होने और अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाने पर काम कर रहा है।

आईपीओ लाने की जल्दी नहीं : फोनपे

नई दिल्ली/पीटीआई

भुगतान सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी फोनपे ने कहा है कि उसे अपना आईपीओ लाने की कोई जल्दी नहीं है और कंपनी के लिए ''जब सही वक्त होगा'' तब वह प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम लायेगी। गौरतलब है कि फोनपे की प्रतिद्वंद्वी पेटीएम सहित कई भारतीय इंटरनेट कंपनियां आने वाले महीनों में आईपीओ लाने की तैयारी में हैं।

फोनपे के सीईओ समीर निगम ने कहा कि जहां तक वित्तीय सेवाओं की बात है तो कंपनी ने अभी ''महज शुरुआत'' की है और वह बीमा जैसे कई क्षेत्रों में संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं।

उन्होंने कहा, ''हम आईपीओ लाने के लिए जल्दी में कभी नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि कंपनी एक क्षेत्र में है, जहां पहले ही भारी विनियमन है और हम वित्तीय सेवाओं में गहराई से पैठ बना रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सही उत्तर यह है कि फोनपे किसी दिन सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन जाएगी ... मैं आईपीओ की पक्की तारीख नहीं बता सकता हूं।''

उन्होंने कहा कि कंपनी आईपीओ के बारे में तब सोचेगी ''जब यह समझ में आएगा कि इसके लिए कोई एक वजह है।''

निगम ने कहा, ''बाजार चक्रीय हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी ठोस कंपनियां हमेशा एक बाजार खोज लेती हैं... क्या मुझे आईपीओ हाथ से चला जाने का डर है, फिलहाल प्रशासनिक पक्ष के अलावा इसकी कोई वजह नहीं। जब भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं हमेशा यही कहता रहूंगा कि जब कोई प्रतियोगी सूचीबद्ध होता है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।

मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं।''जोमैटो ने जुलाई में दलाल स्ट्रीट पर एक शानदार शुरुआत की थी, जिसके शेयर 76 रुपये के निर्गम मूल्य के लगभग 53 फीसदी बढ़ गए थे और इसका बाजार मूल्यांकन एक लाख करोड़ रुपये के पार हो गया था। हाल ही में कारट्रेड ने भी शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की।

इस समय कई इंटरनेट आधारित कंपनी अपने आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं, जिनमें नयका, पेटीएम, पॉलिसीबाजार और ड्रूम शामिल हैं।

फ्यूचर रिटेल-रिलायंस रिटेल सौदा

फ्यूचर रिटेल का कोर्ट से अपील पर जल्द सुनवाई का अनुरोध

नई दिल्ली/पीटीआई

फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी नयी याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि वह एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ 24,731 करोड़ रुपये के विलय के सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने संबंधी पहले के निर्देश को लागू करेगा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की तीन सदस्यीय पीठ ने एफआरएल के वकील से कहा, मुझे फाइल देखने दीजिए और मैं एक तारीख दूंगा।

सिंगापुर की आपातकालीन मध्यस्थता अदालत (ईए) द्वारा एफआरएल को सौदे पर आगे बढ़ने से रोकने वाले आदेश को लागू कराने के लिए अमेजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को कहा था कि अगर चार सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय से कोई स्थगन नहीं मिलता है, तो वह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) को रिलायंस रिटेल के साथ हुए सौदे में आगे बढ़ने से रोकने वाले एकल न्यायधीश के आदेश को लागू करेगा।

उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने 18 मार्च को सिंगापुर आपात पंचाट (ईए) के फ्यूचर रिटेल को, रिलायंस रिटेल को अपना कारोबार 24,713 करोड़ रुपये में बेचने के सौदे पर रोक के आदेश को उचित ठहराया था।

न्यायमूर्ति जे आर मिधा ने फ्यूचर रिटेल को निर्देश दिया था कि वह रिलायंस के साथ सौदे पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करे। अदालत ने कहा था कि समूह ने जानबूझकर ईए के आदेश का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था और साथ ही कंपनी और उसके निदेशकों पर 20 लाख रुपये की लागत भी लगाई थी।

एफआरएल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पीठ से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया और कहा कि अगर शीर्ष अदालत ने उसके पक्ष में आदेश पर रोक नहीं लगाई तो उच्च न्यायालय एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ हुए सौदे में आगे बढ़ने से रोकने वाले एकल न्यायधीश के आदेश को लागू कर देगा।

साल्वे ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के दूरगामी परिणाम होंगे और एफआरएल की अपील पर नौ सितंबर को सुनवाई की मांग की क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष मामला 16 सितंबर को सूचीबद्ध है।

रोहतगी ने एक अन्य याचिका का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पूरी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है और अगर फ्यूचर ग्रुप एवं अन्य को शीर्ष अदालत से अनुकूल आदेश नहीं मिला तो अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

न्यू लॉन्च...

एयरटेल ने 5जी नेटवर्क पर क्लाउड गेमिंग सत्र आयोजित किया

नई दिल्ली/पीटीआई। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने 5जी इंटरनेट पर देश का पहला क्लाउड-गेमिंग सत्र सफलतापूर्वक आयोजित किया है। देशभर में फिलहाल 5जी इंटरनेट का परीक्षण चल रहा है। कंपनी ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए पहले से चल रहे 5जी परीक्षणों के हिस्से के रूप में गुड़गांव के मानेसर में यह गेमिंग सत्र आयोजित किया गया। भारती एयरटेल के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) रणदीप सेखों ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोबाइल गेमिंग एक नया अनुभव है और यह काफी लोकप्रियता हो रहा है। उन्होंने कहा, ''उच्च गति और कम विलंब के संयोजन को देखते हुए क्लाउड गेमिंग 5जी के सबसे बड़े उपयोग के मामलों में एक होगा। यह एक रोमांचक डिजिटल भविष्य की शुरुआत है, जिसे एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए सक्षम करेगा। हम भारत में 5जी इंटरनेट को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।'' क्लाउड गेमिंग दरअसल उपयोगकर्ताओं को बिना किसी गेमिंग हार्डवेयर में निवेश किये रीयल-टाइम में गेम खेलने के साथ गेमिंग का सीधा प्रसारण करने में भी सक्षम करता है। कंपनी ने कहा कि 5जी नेटवर्क की शुरुआत के साथ उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन और टैबलेट पर ही उच्च कंसोल जैसे गेमिंग का अनुभव कर सकेंगे।

यूरोप में व्हाट्सऐप पर रिकार्ड 1950 करोड़ रुपये का जुर्माना

लंदन/पीटीआई। आयरलैंड के निजता वॉचडॉग ने यूरोपीय संघ की एक जांच के बाद व्हाट्सऐप पर रिकॉर्ड 22.5 करोड़ यूरो (1950 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। जांच में पाया गया था कि व्हाट्सऐप ने फेसबुक और अन्य कंपनियों के साथ लोगों के डेटा साझा करने के बारे में यूरोपीय संघ के डेटा संरक्षण नियमों का उल्लंघन किया। डेटा संरक्षण आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह व्हाट्सऐप को उपचारात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश दे रहा है, ताकि उसकी डेटा संस्करण की प्रक्रिया यूरोपीय संघ के नियमों का पालन करे। व्हाट्सऐप ने कहा कि जुर्माना काफी अधिक है और वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। कंपनी ने मीडिया में जारी एक बयान में कहा, ''व्हाट्सऐप एक सुरक्षित और निजी सेवा मुहैया करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने यह सुनिश्चित करने का काम किया है कि हम जो जानकारी देते हैं, वह पारदर्शी और व्यापक हो और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। हम आज के फैसले से असहमत हैं।''

ग्रेनुअल्स इंडिया को डीआरडीओ से कोविड-19 दवा बनाने और विपणन का लाइसेंस मिला

नई दिल्ली/पीटीआई। दवा निर्माता कंपनी ग्रेनुअल्स इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे कोविड-19 के उपचार में काम आने वाली दवा 2-डी ऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) के उत्पादन और विपणन के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ग्रेनुअल्स इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि डीआरडीओ द्वारा विकसित 2-डी ऑक्सी-डी-ग्लूकोज को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) से मध्यम से गंभीर कोविड-19 रोगियों में सहायक चिकित्सा के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति मिली है। उसने कहा कि भारतीय बाजार में इस दवा को जल्द से जल्द लाने के लिए कंपनी डीआरडीओ की टीम के साथ लगातार काम कर रही है। यह दवा मरीज के ठीक होने में लगने वाले औसत समय को ढाई दिन और ऑक्सीजन की मांग को 40 प्रतिशत तक कम कर देती है। ग्रेनुअल्स इंडिया के शेयर बीएसई पर बृहस्पतिवार को पिछले कारोबारी दिवस की तुलनाए में 0.22 प्रतिशत घटकर 344.20 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 5-ओ-21, बेसमेंट, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा - 311001, राजस्थान
सीआईएन - L24121RJ1997PLC029126 फोन नं.- 01482-237104, फैक्स नं. -01482-239638
ई-मेल : secretarial@mbapl.com वेबसाइट : www.mbapl.com
OSTWAL

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यभारत एग्रो प्रोडक्टस लिमिटेड की 24वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") सोमवार, 27 सितंबर, 2021 दोपहर 12:30 बजे (IST)वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो वीडियो मीन के माध्यम से भौतिक कोरम की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। जिसमे एजीएम की विस्तृत सूचना में उल्लेखित व्यवसाय को सम्पादित किया जायेगा।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 31 अगस्त, 2021 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट www.mbapl.com और www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com (ई-वोटिंग प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सेबी के विनियमन 42 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता), 2015 के अनुसार कंपनी ने 20 सितंबर 2021 को आगामी एजीएम में ई-वोटिंग के लिए योग्य सदस्यों का निर्धारण करने और घोषित किए जाने पर इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से रिकॉर्डतिथि / कट-ऑफ तारीख के रूप में निर्धारित किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी के विनियम 44 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार सदस्यों को दूरस्थई-मतदान के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर के एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। सदस्यों के मतदान का अधिकार सोमवार, 20 सितंबर, 2021 (कट-ऑफ तारीख) के अनुसार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उन के द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (सुबह 9 बजे) (आईएसटी) से शुरू होगी और रविवार 26 सितंबर, 2021 (शाम 5.00 बजे) (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल NSDL द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सदस्य www.evoting.nsdl.com पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां "इवेंट" और "कंपनी का नाम" चुना जा सकता है।

एजीएम के नोटिस दूरस्थ ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और एजीएम को वीसी/ओएवीएम के माध्यम उपस्थित हो सकते है। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम का नोटिस भेजने के बाद कंपनी का शेयरधारक बन जाता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही NSDL के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए मैसर्स सौरभ बापना एंड एसोसिएट्स के श्री सौरभ बापना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रूटिनीज़र नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ के मामले में, सदस्य त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ क्यू ज) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ www.evoting.nsdl.com सेले सकते हे, ई-वोटिंग से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायतों के लिए, सदस्य सुश्री प्रियंका बंसल, कंपनी सचिव, मध्यभारत एग्रो प्रोडक्टस लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 5-0-21, बेसमेंट, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा, 311001, राजस्थान, ईमेल secretarial@mbapl.com, फ़ोन: 01482-237104

निर्देशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते मध्य भारत एग्रो प्रोडक्टस लिमिटेड
हस्ताक्षरित /-
(पल्लवी सुखवाल)
कम्पनी सचिव

स्थान- भीलवाड़ा
तिथि- 03/09/2021

कृष्णा फोस्केम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 5-ओ-20, बेसमेंट, आर.सी.व्यास कॉलोनी,भीलवाड़ा - 311001, राजस्थान
सीआईएन - L24124RJ2004PLC019288
OSTWAL

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कृष्णा फोस्केम लिमिटेडकी 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") सोमवार, 27 सितंबर 2021 को सुबह 11:00 बजे (IST)वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो वीडियो मीन के माध्यम से भौतिक कोरम की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। जिसमे एजीएम की विस्तृत सूचना में उल्लेखित व्यवसाय को सम्पादित किया जायेगा।

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 31 अगस्त, 2021 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट www.krishnaphoschem.com और www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com (ई-वोटिंग प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सेबी के विनियमन 42 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता), 2015 के अनुसार कंपनी ने 20 सितंबर 2021 को आगामी एजीएम में ई-वोटिंग के लिए योग्य सदस्यों का निर्धारण करने और घोषित किए जाने पर इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से रिकॉर्डतिथि / कट-ऑफ तारीख के रूप में निर्धारित किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी के विनियम 44 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार सदस्यों को दूरस्थई-मतदान के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर के एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। सदस्यों के मतदान का अधिकार सोमवार, 20 सितंबर,2021 (कट-ऑफ तारीख) के अनुसार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उन के द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 (सुबह 9 बजे) (आईएसटी) से शुरू होगी और रविवार, 26 सितंबर, 2021 (शाम 5.00 बजे) (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल NSDL द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सदस्य www.evoting.nsdl.com पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां "इवेंट" और "कंपनी का नाम" चुना जा सकता है।

एजीएम के नोटिस दूरस्थ ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और एजीएम को वीसी/ओएवीएम के माध्यम उपस्थित हो सकतेहै। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम का नोटिस भेजने के बाद कंपनी का शेयरधारक बन जाता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही NSDL के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए मैसर्स सौरभ बापना एंड एसोसिएट्स के श्री सौरभ बापना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रूटिनीज़र नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ के मामले में, सदस्य त्वरित पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ क्यू ज) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ www.evoting.nsdl.com सेले सकते हे, ई-वोटिंग से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायतों के लिए, सदस्य सुश्री प्रियंका बंसल, कंपनी सचिव, कृष्णा फोस्केम लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 5-O-20, बेसमेंट, आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा, 311001, राजस्थान, ईमेल secretarial@krishnaphoschem.com, फ़ोन: 01482-237104

निर्देशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कृष्णा फोस्केम लिमिटेड
हस्ताक्षरित /-
(प्रियंका बंसल)
कम्पनी सचिव

स्थान- भीलवाड़ा
तिथि- 03/09/2021